

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं और उनका आज केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का कार्यक्रम है। इस दौरान वे प्रदेश में हाल ही में प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान के लिए केन्द्रीय मंत्री से विशेष आपदा पैकेज की मांग करेंगे। इससे पहले कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर उन्हें हाल ही में भारी बारिश से प्रदेश में हुए नुकसान से अवगत करवाया और केंद्र से राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की ऋण सीमा बढ़ाने का भी अनुरोध किया। उधर, मुख्यमंत्री केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से भी मिले और हिमाचल प्रदेश में हवाई सम्पर्क को सुदृढ़ करने को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की।

अवैध कटान

प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद वन व राजस्व विभाग द्वारा शिमला जिले के कोटखाई और कुमारसैन में वन भूमि पर तैयार किए गए सेब के बागीचों को काटा गया है जिससे सेब बागवानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। हिमाचल प्रदेश सेब उत्पादक संघ और किसान सभा ने सेब कटान की कार्रवाई को अवैज्ञानिक करार देते हुए हाईकोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और सरकार से अदालत में सही पक्ष रखने की मांग की है। शिमला में एक पत्रकार वार्ता में किसान नेता राकेश सिंघा ने कहा कि वन भूमि से कब्जे हटाने के नाम पर प्रदेश के किसानों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है।

हम माननीय सामान्य उच्च न्यायालय से उम्मीद करते हैं कि जो अपने मोशन पर ऐसा फैसला उन्होंने दिया है उस पर वो पुनर्विचार करें जिससे जो पेड़ का कटान है, वह समाप्त हो। पेड़ का कट कटान हिमाचल प्रदेश में खास तौर पर जो सबसे बड़ी आर्थिकी है सेब की, पेड़ कटना का मतलब है हिमाचल प्रदेश का स्वयं कटना, हिमाचल प्रदेश की सरकार का दायित्व बनता था कि जो प्रस्ताव उन्होंने विधानसभा में पारित किया, वह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेंगे लेकिन हाईकोर्ट में ऐसा पक्ष नहीं रखा गया यह बहुत दुर्भाग्य है।

जगत सिंह नेगी

दूसरी तरफ राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि वन भूमि पर सेब के पेड़ों के कटान को लेकर जो लोग प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें कानूनी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए।

लोगों ने 2008 से लेकर आज तक जब इन एफ आर ए कानून के तहत दावे पेश करने चाहिए थे मैं समझता हूँ कि शायद उसमें कहीं पीछे रह गए लोग। आजकल जो हाईकोर्ट के फैसले का इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है तो ठीक है और ये ठीक है सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की है। आज भी माननीय उच्च न्यायालय में इस विषय में एडवोकेट जनरल ने जो एक एप्लीकेशन दिया है और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि जो सेब के पेड़ उसमें कुछ समय तक सेब निकालने के लिए रखा जाए परंतु कोर्ट ने ये मानने से इंकार दिया।

किन्नर कैलाश यात्रा

किन्नौर जिला की प्रसिद्ध किन्नर कैलाश यात्रा आज से शुरू हो रही है। ये पैदल यात्रा तांगलिंग गांव से शुरू हो रही है और 14 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद किन्नर कैलाश शिवलिंग तक पहुंचेगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध किए हैं।

ये यात्रा 45 दिन कर दी गई है जबकि इससे पहले 15 दिनों के लिए ही होती थी। समुद्र तल से करीब 6050 मीटर की ऊंचाई पर किन्नर कैलाश पर्वत दिन में कई रंग बदलता है। इस साल भी किन्नर कैलाश यात्रा तांगलिक गांव से ही शुरू होगी यात्रा के लिए सभी श्रद्धालुओं को पंजीकरण पत्र व चिकित्सा प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा इसके लिए सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही अनुमति होगी। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए सभी जरूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तंगलिंग में खड़ा और गुफा के पास स्वास्थ्य टीम मौजूद रहेगी। जिला प्रशासन में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं यह पूरी यात्रा मौसम पर निर्भर होगी।

आकाशवाणी के लिए किन्नर से सुमेश नेगी

मौसम

प्रदेश में मॉनसून के सक्रिय होने से अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने आगामी 20 जुलाई तक प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार कुल्लू और किन्नौर जिला के अलावा बाकी सभी जिलों में अलग-अलग स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है।

राहत

मंडी जिला के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत व पुनर्वास कार्य तीव्र गति से किए जा रहे हैं, ताकि आम जन-जीवन को जल्द सामान्य स्थिति में लाया जा सके। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मदन कुमार ने बताया प्रभावित क्षेत्र में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और उन्हें तात्कालिक राहत स्वरूप खाद्यान्न सामग्री व अन्य जरूरी सामान उपलब्ध करवा दिया गया है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3 आपातकालीन चिकित्सा किट, विभिन्न दवाईयों व इंजेक्शन के 62 बॉक्स चिकित्सा अधिकारी जंजैहली, बगस्याड व करसोग को भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि भारी बरसात और भू-स्खलन से मंडी जिला में बंद सड़क मार्गों को विद्युत ट्रांसफार्मरों और पेयजल योजनाओं को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है।

प्रशिक्षण

चम्बा जिला के पांगी मुख्यालय किलाड़ में बूथ लेवल अधिकारियों व सुपरवाइजर्स की राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारु, पारदर्शी व सटीक रूप से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश और जानकारी प्रदान करना रहा।